पेयजल समस्या से निपटने के लिए कमर कसी

वीडियो कान्फ्रेसिंग में मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

भोपालः मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य ने आने वाले ग्रामीष्मकाल को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आवश्यक पेयजल व्यवस्थाएं करने के निर्देश दियेहैं। मुख्य सचिव आज वीडियो कांफ्रेसिंग कार्यक्रम परख में कलेक्टर्स और कमिश्नर्स से चर्चा कर रहे थे। मुख्य सचिव ने संभागवार पेयजल प्रबंधों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहा कि अप्रैल, मई एवं जून माह में संभावित पेयजल समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 100 करोड़ रूपये की कार्य योजना तैयार की है। प्रदेश में गत एक वर्ष में 20 हजार से अधिक नलकूपों का खनन किया गया है और इस अवधि में लगभग 800 बंद नलज् जल योजनाएं भी फिर से शुरू की गई। समस्त व्यवस्थाओं के बाद भी जिन क्षेत्रों में पेयजल स्त्रोत प्रारंभ न हो सके या पेयजल स्त्रोत उपयोगी सिद्ध न हो सके वहां पेयजल परिवहन की व्यवस्था की जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि परिवहन के लिए वित्तीय साधनों की कमी आड़े नहीं आएगी। परख में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 360 नगरीय निकायों में से 183 निकायों में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति की जा रही है। शेष 177 निकायों में एक अथवा दो दिन के अंतराल से पीने का पानी प्रदाय किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने शिवपुरी, मंदसौर और टीकमगढ़ जिलों के कलेक्टर्स से उनके जिलों की पेयजल समस्याओं की जानकारी मिलने पर उनके निराकरण के निर्देश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिए।

> 100 करोड़ की कार्ययोजना तैयार

नर्मदा नदी से पेयजल जून तक

मुख्य सचिव ने प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से राजधानी में नर्मदा नदी से पेयजल प्रदाय प्रारंभ होने के संबंध में जानकारी प्राप्त की और निर्देश दिए कि जून माह से हर स्थिति में पेयजल प्रदाय प्रारंभ कर दिया जाए। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी ने बताया कि मई माह में पेयजल प्रदाय से संबंधित टेस्टिंग कार्य कर लिया जाएगा और निर्धारित समय पर पेयजल प्रदाय सुनिश्चित किया जाएगा। वितरण प्रणाली से संबंधित आवश्यक कार्य भी अंतिम चरण में है। मुख्य सचिव ने देवास में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति के लिए जरूरी कार्यवाही पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर देवास ने बताया कि वर्तमान में पेयजल आपूर्ति स्थानीय स्त्रोतों से हो रही है। भविष्य में इंदौर नगर निगम के सहयोग से पेयजल आपूर्ति आवश्यक होगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्थाओं के लिए राहत आयुक्त और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आवंटन के लिए प्रस्ताव तैयार करने और मंजूरी लेने पर भी चर्चा हुई।

अप्रैल से जून तक प्रदेश में विद्युत प्रदाय व्यवस्था

मुख्य सचिव श्री वैश्य ने प्रदेश में पर्याप्त विद्युत के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की और उन जिलों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने के निर्देश दिए जो बिजली की बचत एवं विद्युत हानि कम करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा सचिव ने बताया कि गत वर्ष से आठ प्रतिशत अधिक विद्युत आपूर्ति करना संभव हो गया है।